

औद्योगिक प्रगति की ओर अग्रसर, विशाल उत्तर प्रदेश जाग गया है

- **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त-** "विशाल उपभोक्ता आधार, कुशल मानव संसाधन, कई कृषि फसलों का अग्रणी उत्पादक, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास व निवेश हेतु सभी मौलिक आवश्यकताएं विद्यमान हैं। हमने राज्य की विकास दर 10 प्रतिशत लक्षित की है, जिसके लिए 11.2 प्रतिशत की दर से औद्योगिक विकास आवश्यक है"
- **प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग-** उत्तर प्रदेश तेजी से औद्योगिक प्रगति कर रहा है, निवेश व उद्यम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए हम न केवल राज्य की नीतियों व नियमों को बनाया जा रहा है अपितु चुनौती का सामना जमीनी स्तर पर कर रहे हैं"

नई दिल्ली / लखनऊ, 26 अगस्त, 2013:

आठ उत्तर भारतीय राज्यों का निवेश सम्मेलन-इन्वेस्ट नॉर्थ आज नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ (सीआईआई) के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष जयन्त दावर के उद्घाटन भाषण से प्रारम्भ हुआ। सीआईआई द्वारा पार्टनर राज्यों के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखण्ड भाग ले रहे हैं। इसमें लगभग 500 प्रतिभागी, जिसमें भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस एसोसिएशनस सहित पुर्तगाल, हंगरी, कनाडा, र्वाण्डा, इटली, जर्मनी, लेसोथो, ब्रिटेन, पोलैण्ड, सिंगापुर, गाम्बिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैण्ड देशों के आदि के राजनयिक भी हिस्सा ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कर रहे राज्य के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी), आलेक रंजन ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों को उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उपस्थिति निवेशकों व कई बिज़नेस समूहों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए आईआईडीसी ने नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति एवं खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, सौर ऊर्जा, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीतियों में उद्यमियों को उपलब्ध कई आर्थिक और अन्य सुविधाओं के बारे में विशेष रूप से बताया। राज्य में उपलब्ध दक्ष मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और तेजी से विकसित हो रही उच्चस्तरीय अवस्थापना परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित हल के लिए उद्योग बन्धु को सुदृढ़ किया गया है तथा आईटी का उपयोग कर जरूरी स्वीकृतियों व अनापत्तियों को शीघ्रता से जारी करने के लिए व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है।

आईआईडीसी ने कहा-"उत्तर प्रदेश में असीम सम्भावनाएं हैं, राज्य सरकार योजना है। राज्य सरकार सतत प्रयासों के द्वारा इन सम्भावनाओं को साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। औद्योगिक प्रगति की ओर अग्रसर, विशाल उत्तर प्रदेश जाग गया है।" "कनेक्टिविटी दुगुनी करने से विकास तिगुनी गति से होता है", हम मुख्यमंत्री के इस मंत्र का अनुसरण करते हुए सशक्त शासन एवं प्रशासनिक सुधारों की मदद से त्वरित निर्णय, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी की कार्य संस्कृति विकसित कर रहे हैं।"

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दूरदर्शी सोच का संदेश देते हुए आईआईडीसी ने बताया कि यह मुख्यमंत्री की ही पहल थी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रीयल कोरीडोर की तर्ज पर अमृतसर-दिल्ली-कोलकता इंडस्ट्रीयल कोरीडोर (एडीकेआईसी) का विकास किया जाए। उन्होंने कहा-"अमृतसर-दिल्ली-कोलकता इंडस्ट्रीयल कोरीडोर राज्य के औद्योगिक विकास की धुरी सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किए गए अवधारणा दस्तावेज में छह औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं जिनसे प्रदेश में औद्योगिक निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि होने की सम्भावना है।"

आईआईडीसी ने आगे कहा परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रीयल कोरीडोर के अर्ली बर्ड प्रोजेक्टों का विकास आगामी माह से प्रारम्भ कर दिया जाएगा। जिसमें दादरी में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब, बोकाडी में मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब एवं ग्रेटर नोएडा में हाईटेक इंडस्ट्रीयल टाउनशिप सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश केन्द्रित विशेष सत्र- 'एडवान्टेज उत्तर प्रदेश: इनेबलिंग बिज़नेस इनवाइरनमेंट एण्ड प्रोजेक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट' में बोलते हुए प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग-डॉ. शिव प्रताप सिंह ने राज्य में निवेशकों के लिए असीम सम्भावनाओं व विकसित की जा रही सरल व्यवस्था जिससे इन सम्भावनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा-"उत्तर प्रदेश तेजी से औद्योगिक प्रगति कर रहा है, निवेश व उद्यम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए न केवल राज्य की नीतियों व नियमों को बनाया जा रहा है अपितु चुनौती का सामना जमीनी स्तर पर कर रहे हैं।"

उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा—“हम आपकी समस्याओं को टालेंगे नहीं, राज्य सरकार समस्याओं को हल करने के लिए गम्भीर है।” उन्होंने कहा—“अब उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को वीआईपी मानकर व्यवहार किया जाएगा।”

प्रदेश में अपने उद्यमों की सफल एवं प्रगति गाथा सुनाते हुए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के रवीन्द्र जुत्शी तथा मोजर बेअर के वी सी अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण व नये कदमों की भूरी-भूरी प्रशंसा की। रवीन्द्र जुत्शी ने कहा—“पन्द्रह वर्षों में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, डॉ एस पी सिंह पहले ऐसे उच्चाधिकारी हैं, जिन्होंने सैमसंग की इकाई को आकर देखा।” उन्होंने बताया कि सैमसंग जल्दी ही नोएडा में 100 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश से अपनी मोबाइल उत्पादक इकाई का विस्तार करने जा रहा है।

मोजर बेअर के वीसी अग्रवाल ने कहा कि हमें गर्व है कि ग्रे. नोएडा में मोजर बेअर की ऑप्टिकल डिस्क बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी इकाई कार्य रही है। उन्होंने बताया कि मोजर बेअर बुन्देलखण्ड में रु 250 करोड़ के निवेश से सौर ऊर्जा सयंत्र लगा रही है।

प्रतिभागियों एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के मध्य पारस्परिक संवाद भी हुआ, जिसमें उद्योगों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं से अवगत कराया गया। प्रमुख रूप से ऊर्जा, लघु उद्योग, वैकल्पिक ऊर्जा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पर्यटन, सड़क आदि क्षेत्रों के विषय में चर्चा हुई।

उद्यमी जिन्होंने प्रदेश में निवेश की इच्छा व्यक्त की उनमें प्रमुख रूप से वयम टेक्नॉजीस, केईसी इन्टरनेशनल, पटेल इंजिनियरिंग, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमीटर्स एलाएंस आदि थे।

